


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14—जून 20, 2014 (ज्येष्ठ 24, 1936)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14—JUNE 20, 2014 (JYAISTHA 24, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सिंडिकेट बैंक

मणिपाल, दिनांक 21 जनवरी 2014

सं. 261/0089/पीडी:आईआरडी(ओ)/आर.68--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 और 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में आगे संशोधन हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों को सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) संबंधित विनियम में जहाँ कहीं भी वर्णन दिया गया है उसको छोड़कर, ये विनियम 2 जून 2005 से लागू होंगे।

2. सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में -

(i) खंड (छ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् -

‘(छ) “परिवार” का अर्थ अधिकारी की पत्नी/पति (जो बैंक का कर्मचारी नहीं है), पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं) और माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उनपर पूर्णतया आश्रित हैं।’

(ii) खंड (ण) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् -

‘(ण) “पूर्णतया आश्रित बच्चे या माता-पिता” का अर्थ उन बच्चों या माता-पिता से है जिनकी आय प्रतिमाह रु 2,550/- से अधिक नहीं है।’

टिप्पणी :

यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु 2,550 प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय रु 2,550 प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियम में, विनियम 4 के उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् -

(4) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत् होंगे:

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII - रु 29340 - 680 - 30700 - 900 - 3160 - 1000 - 32600
2 1 1

वेतनमान VI - रु 26620 - 680 - 29340
4

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V - रु 24140 - 620 - 26620
4

वेतनमान IV - रु 20480 - 560 - 21040 - 620 - 24140
1 5

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III - रु 18240 - 560 - 21040 - 620 - 22280
5 2

वेतनमान II - रु 13820 - 500 - 14320 - 560 - 19920
1 10

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I - रु 10000 - $\frac{470}{6}$ - 12820 - $\frac{500}{3}$ - 14320 - $\frac{560}{7}$ - 18240

टिप्पणी :

31.10.2002 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवंबर 2002 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ, अन्यथा उप बंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को होंगी ।

(4क) उप-विनियम (1), (2), (3) और (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

4. उक्त विनियम में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् -

5. वेतन वृद्धियां - (1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अधीन, 1 नवंबर 2002 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएगी, अर्थात् -

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (4) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएगी ।

(ख) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतन वृद्धि(याँ) सहित आगे की वेतन वृद्धियां नीचे खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएगी, बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें ।

(ग) ऊपर खंड (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुँचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(याँ) दी जाएगी । वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुँच चुके अधिकारियों के मामले में रु 560/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान III, के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु 620/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

परंतु, 1 नवंबर 1994 को और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी ।

परंतु आगे ऐसी वेतन वृद्धि(यां) अगले उच्च वेतनमान/अवरोध वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जिसने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया हो ।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा । ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान । तथा ॥ के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, इयूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

- (2) सीएआईआईबी का भाग 1 / भारतीय बैंकर संस्थान की ज्यूनियर एसोसिएट और भाग ॥ भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

- (क) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा का भाग । या भाग ॥ उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी, बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो ।
- (ख) 01 नवंबर 1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

तालिका

जिन्होंने <u>सीएआईआईबी</u> का केवल भाग । उत्तीर्ण किया है	(i) एक वर्ष पश्चात् रु 100/- प्रति माह, जिसमें से रु 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
जिन्होंने <u>सीएआईआईबी</u> के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(ii) एक वर्ष पश्चात् रु 100/- प्रति माह, जिसमें से रु 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
	(iii) एक वर्ष पश्चात् रु 250/- प्रति माह, जिसमें से रु 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।

- (ग) 01 नवंबर 1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित होंगी :

तालिका

जिन्होंने <u>सीएआईआईबी</u> का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 120/- प्रति माह ।
जिन्होंने <u>सीएआईआईबी</u> के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 120/- प्रति माह ।
	(iii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु 300/- प्रति माह ।

परंतु, विनियम 5(3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे ।

(घ) 1 नवंबर 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित होंगी:

जिन्होंने <u>जेएआईआईबी</u> या <u>सीएआईआईबी</u> का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 150/- प्रतिमाह ।
जिन्होंने <u>जेएआईआईबी</u> और <u>सीएआईआईबी</u> या <u>सीएआईआईबी</u> के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 150/- प्रतिमाह ।
	(iii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु 360/- प्रतिमाह ।

परंतु, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं तथा उन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियां मंजूर की गई हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे ।

(ड) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित होंगी:

तालिका

जिन्होंने <u>जे.ए.आई.आई.बी.</u> या <u>सी.ए.आई.आई.बी.</u> का भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 300/- प्रतिमाह ।
जिन्होंने <u>सी.ए.आई.आई.बी.</u> के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु 300/- प्रतिमाह ।
	(iii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु 750/- प्रतिमाह ।

परंतु, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं तथा उन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियां मंजूर की गई हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे ।

टिप्पणी :

- (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भुगतान मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जे.ए.आई.आई.बी./सी.ए.आई.आई.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भुगतान पाने का पात्र होगा।
- (ii) 1 नवंबर 1994 को तथा उसके बाद से, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।
- (iii) वैसे अधिकारी व्यावसायिक अर्हता भुगतान के लिए उपर्युक्त अनुसार पात्र नहीं होंगे जिन्होंने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया हो ।
- (iv) यदि कोई अधिकारी अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद जे.ए.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. (कोई एक भाग या दोनों) की योग्यता प्राप्त करता है तो, उन्हें योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता भुगतान की पहली किस्त दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता भुगतान के बाद की किस्त का निर्मोचन इसकी पहली किस्त के निर्मोचन की तारीख से संदर्भित होगा ।
- (v) यदि किसी अधिकारी ने खंड (iv) में वर्णित योग्यता में से किसी एक को 02 जून 2005 की स्थिति में प्राप्त कर लिया है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने के एवज में कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता भुगतान हासिल नहीं की है, उन्हें 01 नवंबर 2002 या ऐसी अर्हता प्राप्त

करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से उपर्युक्त दिए गए दर के अनुसार व्यावसायिक अर्हता भुगतान निर्माचित किया जाएगा ।

- (3) (क) जो अधिकारी 1 नवंबर 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी । जो अधिकारी 1 नवंबर 1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी ।

टिप्पणी - अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 1 नवंबर 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (यां) प्राप्त कर चुका है, वह 1 नवंबर 1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 1 नवंबर 1993 को देय महंगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की राशि के जोड़ के बराबर होगा । यहां नीचे दिए गए सारणी के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, अगले परिशोधन तक वैध रहेगा ।

सारणी

वेतनवृद्धि घटक	01 नवंबर 1993 को <u>महंगाई</u> <u>भत्ता</u>	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल <u>नियत वैयक्तिक भत्ता</u>
(क) रु	(ख) रु	(ग) रु
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(ग) 01 नवंबर 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित निम्नानुसार दिया जाएगा :

सारणी

वेतन वृद्धि घटक	01 नवंबर 1997 को <u>महंगाई</u> <u>भत्ता</u>	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल <u>नियत वैयक्तिक भत्ता</u>
(क) रु	(ख) रु	(ग) रु
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

(घ) 01 नवंबर 2004 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक भत्ता के साथ-साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, नीचे दिए गए सारणी के अनुसार होगा और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगा ।

सारणी

वेतन वृद्धि घटक	01 नवंबर 2002 को <u>महंगाई भत्ता</u>	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहाँ देय कुल <u>नियत वैयक्तिक भत्ता</u>
(क) रु	(ख) रु	(ग) रु
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी :

- (i) विनियम 5 के उप-विनियम 3 के खंड (ख), (ग) एवं (घ) में सारणी के कॉलम (ग) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है ।
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन विनियम 4 के उप-विनियम (2) और (3) में विनिर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की वेतनवृद्धि घटक पर (अ) +(आ) +संबद्ध अधिकारी द्वारा विनियम 5 के उप-विनियम 3 के खंड (ख), (ग) एवं (घ) में निर्दिष्टानुसार आहरित मकान किराया भत्ता होगा ।
- (iii) 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद से, नियत वैयक्तिक वेतन देने के कारण उप-विनियम (2) के अधीन स्पष्टीकरण के अनुसार व्यावसायिक अर्हता भुगतान करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

परंतु, जहां व्यावसायिक अर्हता भुगतान भी कोई किस्त, जो पूर्व के प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक बढ़ा दी गई थी और 1 नवंबर 1999 को या उसके बाद जारी की जाने वाली है, अधिकारी को इस तारीख को या से दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता भुगतान, यदि कोई हो, की दूसरी किस्त 1 नवंबर 2000 को दी जाएगी ।

- (iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा ।

- (ड) जिस अधिकारी को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर खंड (ख), (ग) या (घ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी ।

5. विनियम 21 के उक्त विनियमों में, उप-विनियम 3 के बाद निम्नलिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा ;
(4) 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी:

(क) अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार पर 1960=100 के तिमाही औसत में 2288 अंकों से अधिक प्रति 4 अंकों के उतार या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता देय होगा ।

(ख) 01.11.2002 से 31.01.2005 की अवधि के दौरान निम्न दरों पर महंगाई भत्ता देय होगा :

i. रु 9,650 तक 'वेतन' का 0.18% +

ii. रु 9,650 से अधिक और रु 15350 तक 'वेतन' का 0.15% +

iii. रु 15350 से अधिक और रु 16350 तक 'वेतन' का 0.09% +

iv. रु 16350 से अधिक 'वेतन' का 0.04%

(ग) 01 फरवरी 2005 को या उसके बाद से, महंगाई भत्ता वेतन का 0.18% देय होगा :

टिप्पणी:

(अ) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' में मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(आ) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ) और (ड) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा ।

6. विनियम 22 के लिए उक्त विनियम में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

22. मकान किराया भत्ता -

(1) (क) 01 नवंबर 1999 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।

(ख) 1.11.1999 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा ।

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 9% प्रति माह
(ii) क्षेत्र I के स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 8% प्रति माह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले सभी स्थान	वेतन का 7% प्रति माह

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतन मान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, देय होगा।

- (2) (क) 01.11.2002 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) 1.11.2002 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्न तालिका के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

तालिका

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख 'ए' वर्ग के नगरों तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) क्षेत्र I के स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतन मान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा।

- (3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो उसे उप-विनियम (1) (ख) और (2) (ख) में उल्लिखित परंतुक के आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह नीचे (अ) अथवा (आ) में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो ।

‘अ’

निम्नलिखित का योग :

- i) निवास स्थान के लिए देय नगरपालिका कर, और
- ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किंतु इसके अंतर्गत वातानुकूल जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे; या

‘आ’

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य ।

स्पष्टीकरण-

- (1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु ‘मानक किराया’ से अभिप्रेत है:

(क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में सरकार में ऐसे निवास स्थानों के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया,

(ख) जहाँ आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो, बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त (क) में बताई गई कार्यविधि के अनुसार परिकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो ।

- (2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु ‘वेतन’ का तात्पर्य मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियों से है।

(3) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को 01 नवंबर 1994 से प्रभावी गिना जाएगा ।

- (4) इस विनियम और विनियम 23 के उप-विनियम (1) तथा (2) के प्रयोजन हेतु, क्षेत्र I और क्षेत्र II के निम्न अभिप्राय हैं :

क्षेत्र I : 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र II : वे सभी स्थान जो क्षेत्र-I में शामिल नहीं किए गए हैं ।

7. विनियम 23 के लिए उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

23. अन्य भत्ते:

(1) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, अधिकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4%, अधिकतम रु 540/- प्रति माह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते	मूल वेतन का 3%, अधिकतम रु 375/- प्रति माह
(क) अन्य स्थान	शून्य

(2) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार होगी ।

(3) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी गुप ए या गुप बी की किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो, वह निर्धारित गुप ए या गुप बी में क्रमशः रु 210 प्रतिमाह या रु 185 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा ।

(4) 01 जनवरी 2004 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में किया जाता है और पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए रु 500 प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता देय होगा ।

परंतु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ।

(5) 1 जून 2005 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है । विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75%, अधिकतम रु 1500/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते ।

परंतु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु 750/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु 750/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

- (6) यदि किसी अधिकारी से कम से कम 7 दिन लगातार या किसी कैलेंडर महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए, यथानुपात, उसके वेतन का 6% स्थानापन्न भत्ता मिलेगा । स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि/पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा किंतु अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं ।

परंतु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के मात्र पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा ।

- (7) यदि किसी अधिकारी को ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है जहाँ 01 अप्रैल तथा 30 सितंबर को बहियां बंद की जाती हैं तो उसे दोनों लेखाबंदी हेतु रु 250/- का लेखाबंदी भत्ता देय होगा ।
- (8) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, यदि दिन में उसके कार्य समय में न्यूनतम 2 घंटे के लिए विखंडन किया जाता है तो उसे रु 125/- प्रतिमाह सेवा विखंडन भत्ता देय होगा ।
- (9) यदि वह अवकाश के दिन वाल्ट या तिजोरी के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है तो उस पर लागू दर से उसे “डाइम भत्ता” देय होगा ।

- (10) 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी नीचे दी गई तालिका के स्तंभ के 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवा कर रहा हो तो उसे स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा :

तालिका

स्थान	दर
1	2
(i) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतनमान का 5% अधिकतम रु 1150 प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2 ^{1/2} % अधिकतम रु 500 प्रतिमाह
(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर	वेतन का 2% अधिकतम रु 400 प्रतिमाह

टिप्पणी :

- (क) कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थान जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केंद्रों के लिए देय दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा ।
- (ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केंद्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे ।

परंतु, जो अधिकारी 1 मई 1989 के पूर्व ऐसे केंद्र पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी केंद्र पर तैनात रहता है उसे 30 अप्रैल 1989 को मिल रहे भत्ते की प्रमात्रा संरक्षित की जाएगी और उसी वेतनमान में उस केंद्र में उसके तैनात रहने तक प्रतिमाह अदा की जाएगी ।

8. विनियम 24 के लिए, उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

24. चिकित्सा सहायता:

(1) हर अधिकारी को अपने व अपने परिवार हेतु उसके द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :

(क) चिकित्सा व्यय :- तारीख 01 फरवरी 2004 को और उसके बाद से निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित श्रेणी में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट सीमा के आधार पर की जाएगी । यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए घोषणापत्र में उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप की जाएगी :

तालिका

श्रेणी	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु 3750 या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु 5000 या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो

टिप्पणी -

- (i) अधिकारी अनुपभोक्त चिकित्सा व्यय का संचयन कर सकता है जो उपर्युक्त अधिकतम रकम की तीन गुना रकम से अधिक न हो जाए ।
- (ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता के अधीन चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों अर्थात् फरवरी 2004 से दिसंबर 2004 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के उद्देश्य के लिए किसी अधिकारी के “परिवार” का अर्थ विनियम 3 के खंड (जी) में दिए गए परिभाषा के अनुसार होगा ।

- (ख) (i) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
- (ii) 01 मई 2005 को या उसके बाद से इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के चिकित्सालयवास व्ययों की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 02 जून 2005 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते वह नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित सीमा के अधीन हो:-

सारणी

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	(i) बिस्तर शुल्क स्वयं - रु. 600/- प्रति दिन परिवार - रु. 450/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार - कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	(i) बिस्तर शुल्क स्वयं - रु. 800/- प्रति दिन परिवार - रु. 600/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार - कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर

- (2) उपरोक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा सुविधाओं (चिकित्सालयवास सहित) को इनके स्थानापन्न के रूप में नियत तिथि को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं (चिकित्सालयवास सहित) के अपरिवर्तित रूप में मंडल द्वारा स्वीकार किया जा सकता है । तदनुसार मंडल द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने पर नियत तिथि को चिकित्सा सुविधाएं (चिकित्सालयवास इत्यादि सहित) प्रदान करने हेतु प्रचलित नियम व प्रावधानों के अधीन ही सभी अधिकारी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।
- (3) चिकित्सा व्यय तथा चिकित्सालयवास सुविधा उन अधिकारियों के संबंध में भी स्वीकार्य है जिन्हें निलंबनाधीन रखा गया है ।
9. विनियम 25 के लिए, उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

25. आवास व्यवस्था :-

(1) अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा ।

(2) किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवंबर 2002 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.75% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करेगा ।

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.4% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।

परंतु, जहाँ बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहाँ बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

10. विनियम 41 के, उक्त विनियमों में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे-

(1) 02 जून 2005 को और उसके बाद से, कार्यवश यात्रा के दौरान कोई अधिकारी निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे :

- (i) कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी में कार्यरत एक अधिकारी, रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में या एसी 2-टीयर स्लीपर में यात्रा कर सकता है । तथापि, वह विमान द्वारा (किफायती दर्जा), यात्रा कर सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी से कारोबार की आवश्यकता या लोक हित की दृष्टि से अनुमति दी जाती है ।
- (ii) मध्य प्रबंध श्रेणी में कार्यरत एक अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में या एसी 2-टीयर स्लीपर में यात्रा कर सकता है । तथापि, वह विमान द्वारा (किफायती दर्जा), यात्रा कर सकता है, यदि यात्रा की जानेवाली दूरी 500 कि.मी. से अधिक हो । तथापि, वह कम दूरी के संबंध में भी विमान द्वारा (किफायती दर्जा) यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी से कारोबार की आवश्यकता या लोक हित की दृष्टि से यात्रा करने के लिए अनुमति दी जाती है ।
- (iii) वरिष्ठ प्रबंध या उच्च कार्यपालक श्रेणी में कार्यरत एक अधिकारी रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या विमान द्वारा (किफायती दर्जा) यात्रा कर सकता है।
- (iv) वरिष्ठ प्रबंध या उच्च कार्यपालक श्रेणी में कार्यरत अधिकारी, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेल अथवा विमान उपलब्ध न हो तो कार द्वारा यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि स्थानों के बीच की दूरी 500 कि.मी. से अधिक न हो । तथापि, दोनों स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी को रेल, अथवा विमान द्वारा तय करना संभव होने पर केवल शेष दूरी की यात्रा, सामान्यतः कार द्वारा की जानी चाहिए ।

- (v) कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी अधिकारी को निजी वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमति प्रदान कर सकता है ।
- (ख) उप-विनियम (4) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे :
- (क) विराम भत्ता -
- 01 जून 2005 को और उसके बाद से नीचे दी गई सारणी के अनुसार कोई अधिकारी प्रतिदिन विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

सारणी

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2		
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु 600	रु <u>550</u>	रु <u>500</u>
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	550	<u>500</u>	<u>400</u>

परंतु वेतनमान IV और उनसे उच्च अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यानि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन रु 700/- की दर से विराम भत्ता देय होगा ।

परंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

स्पष्टीकरण - विराम भत्ता की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो ।

11. विनियम 42 के उक्त विनियमों में, उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे -
- (3) पहली अप्रैल 1997 को और उस तारीख से स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा :

सारणी

श्रेणी	एकमुश्त राशि
वरिष्ठ प्रबंध और उच्च कार्यपालक	रु. 5000
कनिष्ठ प्रबंध और मध्य प्रबंध	रु. 4,000

परंतु, 01 मई 2005 को और उसके बाद से यह उप-विनियम के प्रावधान तभी लागू होंगे जब रु “5000” एवं रु “4000” के आंकड़ों को क्रमशः रु “8750” एवं रु “7000” से प्रतिस्थापित कर दिया जाए ।

12. विनियम 44 के लिए, उक्त विनियमों में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

44. अवकाश पर यात्रा रियायत:

- (1) चार वर्ष की प्रत्येक अवधि में अधिकारी अपने अधिवास तक यात्रा के लिए अवकाश पर यात्रा रियायत का लाभ, प्रति द्विवार्षिक खंड में एक बार, प्राप्त कर सकता है । विकल्पतः दो वर्ष के एक ब्लॉक में वह अपने अधिवास को जा सकता है और एक ब्लॉक में निकटतम मार्ग से भारत में किसी स्थान को जा सकता है ।
- (2) अधिकारी, चार वर्ष या दो वर्ष की अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान कभी भी अपने अवकाश यात्रा रियायत (अधिवास की यात्रा को छोड़कर) को समर्पण करके नकद भी ले सकते हैं जिसके अंतर्गत रेल द्वारा यात्रा की श्रेणी के लिए पात्र किराए के 75% की समतुल्य राशि प्राप्त करने की हकदार होंगे, इसमें जे.एम.जी.एस. I तथा एम.एम.जी.एस II एवं III के अधिकारियों के लिए पात्र दूरी 4500 कि.मी. (एकतरफा) है और एस.एम.जी.वेतनमान IV एवं उच्च अधिकारियों के लिए 5500 कि.मी. (एकतरफा) है । अपना अवकाश यात्रा रियायत भुनाने का विकल्प लेते समय अपना और अपने परिवार सदस्यों के लिए उस अवधि के दौरान एक ही बार दावा प्रस्तुत करें । अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा भुनाते समय साधिकार छुट्टी को भी भुनाने की सुविधा मिलेगी ।
- (3) अवकाश यात्रा रियायत में अधिकारी उसी श्रेणी व साधन द्वारा यात्रा कर सकता है, जिसमें वह स्थानांतरण होने पर यात्रा करने के लिए पात्र है और अधिकारी को अवकाश यात्रा रियायत, मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी अन्य नियम व अनुबंधों के अधीन उपलब्ध किया जाना होगा ।
- (4) चार वर्ष में एक बार अधिकारी द्वारा अवकाश पर यात्रा रियायत का उपयोग करते समय उसे, अधिकतम एक समय पर एक माह के साधिकार अवकाश को अभ्यर्पित करते हुए नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है, विकल्पतः दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास को जाते समय और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी जगह को जाते समय उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों की या एक ही ब्लॉक में 30 दिनों की साधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए अनुमति दी जा सकती है । छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के लिए, अवकाश पर यात्रा सुविधा आरंभ होने के महीने के दौरान देय सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी ।

परंतु यदि एक अधिकारी अपने विकल्प पर प्रधानमंत्री की राहत निधि को दान करना चाहता है तो, उस एक दिन का अतिरिक्त साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए अनुमति दी जाएगी जो अधिकारी द्वारा बैंक को इसके संबंध में पत्र देने तथा रकम प्रेषित करने के प्रति बैंक को प्राधिकृत किए जाने के अधीन होगा ।

सिंडिकेट बैंक-(अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची

विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें

अधिकारी, दि. 1 नवंबर 2002 से विशेष क्षेत्रीय भत्ते, जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे:-

तालिका

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
1.	मिजोरम	(रु.)	(रु.)
	(क) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र	1,000	1,300
	(ख) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला	800	1,050
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला	600	750
2.	नागालैंड	800	1,050
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
	(क) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	800	1,050
	(ख) उत्तर एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीपसमूह	1,000	1,300
4.	सिक्किम	1,000	1,300
5.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	1,000	1,300
6.	असम	160	200
7.	मेघालय	160	200

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र	800	1,050
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा त्रिपुरा	600	750
9.	मणिपुर	600	750
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र	1,000	1,300
	(ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा अरुणाचल प्रदेश	800	1,050
11.	जम्मू और कश्मीर		
	(1) कठुआ जिला	1,000	1,300
	(क) नियाबत बानी		
	(ख) लोही		
	(ग) मलहार		
	(घ) मछोड़ी		
	(2) (क) उधमपुर जिला	1,000	1,300
	i. दुडु बसंतगढ़		
	ii. लांडर भामाग इलाका		
	iii. थक्रकोट		
	iv. नगोट		
	(ख) 2 (ग) में सम्मिलित को छोड़कर मोहरे तहसिल के सभी क्षेत्र	1,000	1,300
	(ग) मोहरे तहसिल के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नास तक के क्षेत्र ।	800	1,050

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
	(3) डोडा जिला किश्तवार तहसिल के नियाबत नवगम तथा पद्देर के इलाके	1,000	1,300
	(4) लेह जिला जिले के सभी स्थान	1,000	1,300
	(5) बारामुला जिला क) संपूर्ण गुरेज-निराबत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका	1,000	1,300
	ख) मछिल	800	1,050
	(6) पूंछ तथा रजौरी जिला पूंछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र	600	750
	(7) उपर्युक्त (1) से (6) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी की दूरी में आनेवाले ऐसे स्थान जहाँ सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र घोषित किया गया है ।	600	750
	हिमाचल प्रदेश (1) चंबा जिला 1 (क) पंगी तहसिल 1 (ख) भारमौर तहसिल के निम्नलिखित गांव तथा पंचायत (i) पंचायत : बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नयागाम तथा टुंडा	1,000 800	1,300 1,050

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
	<p>(ii) गांव : जगत ग्राम पंचायत का घाटु, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी</p> <p>2. भरमौर तहसिल, उपर्युक्त भाग 1 ख में शामिल गावों एवं पंचायतों को छोड़कर</p> <p>3. भटियाट तहसिल का झंडु पंचायत, चुराह तहसिल, डलहौजी टाउन (बनिखेत सहित)</p> <p>(2) किन्नौर जिला :</p> <p>(क) आश्रंग, चिटकुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रूपी के ग्राम पंचायत हैं, पूह सब-डिविजन, उपर्युक्त पंचायत क्षेत्र को छोड़कर</p> <p>(ख) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिला</p>	<p>600</p> <p>1,000</p> <p>600</p>	<p>750</p> <p>1,300</p> <p>750</p>
	<p>(3) कुल्लू जिला :</p> <p>3 (क) निर्माद तहसिल के 15/20 क्षेत्र जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं</p>	<p>1,000</p>	<p>1,300</p>

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
	3 (ख) आउटर-सेराज (निर्माद तहसिल के बरौ तथा जकत-खाना के गावों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रबिस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्माद तहसिल के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शामिल कर)	600	750
	(4) लाहौल तथा स्पिति जिला : लाहौल तथा स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र	1,000	1,300
	(5) शिमला जिला : (क) रामपुर तहसिल के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना सदाना, सरपारा तथा चडी-ब्रांदा के पंचायत शामिल हैं ।	1,000	1,300
	(ख) दोड़ा-कावर तहसिल, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसिल तथा मुनिश, परगना सराहान का घोरी चाइबिस	800	1,050
	(ख) चोपल तहसिल तथा घोरिस, पंजगांव, पाटस्नौ, नौबिस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का द्योती ग्राम पंचायत, परगना बराबिस, रामपुर कस्बा तथा रामपुर तहसिल के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसुमपती, मशोब्रा, तारादेवी एवं टुटु)	600	750

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
	(6) कांगड़ा जिला :		
	(क) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र	800	1,050
	(ख) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय - महिला आईटीआई, दारी, मेकनिकल वर्कशोप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशोप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, बिनवा परियोजना, शामनगर, कार्यालय / जर्सी फार्म, बनूरी, सेरिकल्चर कार्यालय / इंडो-जर्मन एग्रिकल्चर वर्कशोप / एचपीपीडब्ल्यूडी डिविजन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब-डिविजन, लोहना, डीपीओ निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एपीएसईई डिविजन, घुग्गर	600	750
	(7) मंडी जिला :		
	जोगिंदर नगर तहसिल का छुहर घाटी, थुनाग के पंचायत	600	750

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
	बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना के तहसिल, धरमपुर ब्लॉक के पंचायत - बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, कर्सोंग तहसिल के पंचायत - बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी, सैंज, साराहन, तेबान, सुंदरनगर तहसिल के पंचायत - बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी, शोजा		
	(8) सिरमौर जिला :		
	(क) बनी, बखाली (पाछड़ तहसिल), भड़ोग, भेनेड़ी (पौंटा तहसिल), बिड़ला (नाहन तहसिल), डिब्बड़ (पाछड़ तहसिल) और थाना कसोगा (नाहन तहसिल) के पंचायत	600	750
	(ख) थानस्मिरी ट्रैक्ट		
	(9) सोलन जिला :	600	750
	मंगल पंचायत		
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	160	200

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		रु.10,000 से रु.14,000 के वेतन के लिए	रु.14,001 और उससे अधिक के वेतन के लिए
13	उत्तर प्रदेश : चमोली, पिथौड़ागढ़ और उत्तरकाशी जिलों के क्षेत्र 2(क) पिथौड़ागढ़ और उत्तरकाशी जिले का अन्य क्षेत्र (उत्तरकाशी का जिला मुख्यालय शामिल) 2(ख) चंपावत जिला (लोहाघाट का क्षेत्र शामिल)	1000	1300
14	उत्तरांचल : रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले के क्षेत्र	800	1,050

एस बालकृष्णन
महा प्रबंधक (का)

नोट: सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 के उपर्युक्त विनियम में पूर्ववर्ती संशोधन नीचे
दिये गए विवरण के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

क्रम सं	राजपत्र अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	16	09.06.1990
2.	16	20.04.1991
3	23	06.06.1992
4.	29	17.07.1996
5.	44	01.11.1996
6.	47	23.11.2002

SYNDICATE BANK

Manipal, the 21st January 2014

No.261/0089/PD:IRD(O)/R.68--In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Syndicate Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.
2. In the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3, -

- (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely, -

'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer;';

- (ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs. 2,550 per month'

Note: If the income of one of the parents exceeds Rs. 2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;'

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under: -

- (a) Top Executive Grade:

$$\text{Scale VII} = \text{Rs. } 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{Scale VI} = \text{Rs. } 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

- (b) Senior Management Grade:

$$\text{Scale V} = \text{Rs. } 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{Scale IV} = \text{Rs. } 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

- (c) Middle Management Grade:

$$\text{Scale III} = \text{Rs. } 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{Scale II} = \text{Rs. } 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

- (d) Junior Management Grade:

$$\text{Scale I} = \text{Rs. } 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240.$$

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

'5. Increments. – (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;
- (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs. 560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 620 for officers in the last stage of Scale III:

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits;
	(ii) Rs.250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale; (ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale; (ii)Rs.750- per month after two years on reaching maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

- (3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note: (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale”:

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

‘(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :-

- (i) 0.18% of ‘pay’ upto Rs. 9,650 plus
- (ii) 0.15% of ‘pay’ above Rs. 9,650 and upto Rs. 15,350 plus
- (iii) 0.09% of ‘pay’ above 15,350 and upto Rs. 16,350 plus
- (iv) 0.04% of ‘pay’ above Rs. 16,350

(c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) “Pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) (Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.’

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

‘22. House Rent Allowance – (1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major ‘A’ class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Governemnt and Project Area Centres in Group ‘A’.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group ‘B’.	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in

which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

- (2) (a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

	Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
	(1)	(2)
(i)	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

- (3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of: -

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:-

- (1) For the purpose of this regulation "standard rent" means: -
- (a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
- (b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.

- (2) “Pay” for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under :-
- Area I - Places with a population of more than 12 lakhs
- Area II - All places not included in Area – I.’.

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely :-

‘23. Other Allowances:

- (1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely:

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

- (2) On and from the 1st day of November, 2002, the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st April and the 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.
- (8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month.

Note : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.’.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

‘24. Medical Aid:-

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-
- (a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own

certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation : - “Family” of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

(b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.600 per day. Family – Rs.450 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.800 per day. Family – Rs.600 per day.</p> <p>(ii) Other charges –</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>

- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)
- (3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.
9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-
- ‘25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.
- (2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:.
- Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:
- Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.’.
10. In the said regulations, in regulation 41, - for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-
- ‘(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-
- an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
 - an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
 - an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).
 - an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
 - any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle.
- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- (a) Halting Allowance - On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to `per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs.550	Rs.500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation : For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

- ‘(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Management and Junior Management	Rs.4,000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures “Rs.5000” and “Rs.4000”, the letters, words and figures “Rs.8750” and “Rs.7000” had been respectively substituted.’

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

‘44 Leave Travel Concession:

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.’

Schedule to Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979

See, sub-regulation (2) of regulation 23

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

TABLE

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
10	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh (b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	1,000 800	1,300 1,050
11.	Jammu and Kashmir (1) Kathua District (a) Niabat Bani (b) Lohi (c) Malhar (d) Macchodi	1,000	1,300
	(2) (a) Udhampur District i. Dudu Basantgarh ii. Lander Bhamag Illaqa iii. Thakrakote iv. Nagote (b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c). (c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1,000 800	1,300 1,050
	(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa (b) Matchill (6) Poonch and Rajouri District :	1,000 800	1,300 1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	1(a) Pangi Tehsil	1,000	1,300
		800	1,050
	1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil		
	(i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah		
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above.	600	750
	3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).		
	(2) Kinnaur District:		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division,	1,000	1,300

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(b) excluding the Panchayat Areas specified above.	600	750
	(c) Entire District other than Areas included in (a) above		
	(3) Kullu District:		
	3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District :		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghorī Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghorī Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhagal and Chhota Bhagal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar.Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag	600	750
	Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.		
	(8) Sirmaur District:		
	(a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).	600	750
	(b) Thansgiri Tract		

Serial number		Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000 to Rs.14,000	Pay from Rs.14,001 and above
	Places where the allowance is payable		
	(9) Solan District : Mangal Panchayat.	600	750
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	160	200
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts: 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi). 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14.	Uttaranchal: Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800	1,050

S BALAKRISHNAN
General Manager (P)

Notes: The principal regulations were published in the official Gazette on the ____ and subsequent amendments were notified vide the following notifications:

Sr. No.	Gazette Notification No.	Date
1.	No. 16	09.06.1990
2.	No. 16	20.04.1991
3.	No. 23	06.06.1992
4.	No. 29	17.07.1996
5.	No. 44	02.11.1996
6.	No. 47	23.11.2002

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in